

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पोलैंड यात्रा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पोलैंड यात्रा 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। महत्वपूर्ण राजनयिक कदम के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 अगस्त को पोलैंड पहुंचे। यह इस देश में 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। इस ऐतिहासिक यात्रा से भारत-पोलैंड संबंधों का बढ़ता महत्व रेखांकित होता है। लगभग 70 वर्ष पहले स्थापित हुए इन संबंधों ने काफी प्रगति की है। भारत और पोलैंड के बीच समृद्ध राजनयिक इतिहास है जिसकी शुरुआत 1950 के दशकारंभ में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तथा पोलैंड के द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से उबरने के बाद हुई थी। दोनों देशों ने 1954 में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित कर परस्पर सम्मान, साझा मूल्यों तथा समान हितों पर आधारित साझेदारी की नीव रखी थी। शीतयुद्ध के दौरान भी भारत और पोलैंड के बीच हार्दिक संबंध बने रहे जिनको गुटनिरपेक्ष आंदोलन में उनकी सदस्यता से बल मिलता था। इस कालखंड में द्विपक्षीय व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा राजनीतिक संवाद में थाई प्रगति हुई। लेकिन शीतयुद्ध समाप्त होने के बाद इन संबंधों में थोड़ी 'सुस्ती' आई क्योंकि दोनों देश घरेलू सुधारों तथा आर्थिक परिवर्तनों पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच संबंधों की गरमाहट बनी रही। हालिया वर्षों में भारत-पोलैंड संबंधों में तेजी से प्रगति हुई। यह परस्पर आर्थिक हितों, वैश्वक सुरक्षा के प्रति साझा सरोकारों तथा बहुपक्षीयता के प्रति प्रतिबद्धता से संचालित हैं। यूरोपीय संघ के सदस्य के रूप में पोलैंड की मध्य यूरोप में प्रमुख भूमिका है और वह इस क्षेत्र से संपर्क करने में भारत का महत्वपूर्ण साझेदार बना हआ है। इस बीच भारत की तेज आर्थिक प्रगति तथा



सहयोग बढ़ने की उम्मीद है जिनमें व्यापार एवं निवेश, रक्षा, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान शामिल हैं। भारत और पोलैंड के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है और द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्षों में लगभग 3 बिलियन डालर तक पहुंचा है। पोलिश कंपनियों ने भारतीय बाजार व खासकर रक्षा, ऊर्जा और ढांचागत संरचना क्षेत्रों में काफी दिलचस्पी दिखाई है। इसी प्रकार भारतीय उद्यमी पोलैंड में खासकर सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और विनिर्माण में अवसर खोज रहे हैं। रक्षा सहयोग परस्पर हित का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस दृष्टिकोण से बढ़ते रक्षा उद्योग वाला देश भारत पोलैंड का महत्वपूर्ण साझेदार बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पोलैंड में बड़ी संख्या में अनिवासी भारतीय हैं और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ रहा है। पोलैंड में भारतीय फिल्में, भोजन और त्योहार लगातार लोकप्रिय होते जा रहे हैं जिससे दोनों देशों की जनता के बीच बढ़ते संपर्कों का पता चलता है। भारत और पोलैंड एकसाथ अनेक साझा चुनौतियों को संबोधित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं जिनमें वैश्विक सुरक्षा से लेकर जलवायु परिवर्तन तक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नेन्द्र मोदी की यह पोलैंड यात्रा ज्यादा गतिशील व परस्पर लाभदायक साझेदारी बढ़ाने में अपना योगदान करेगी।

भावी मानसून की विभीषिका से जीवन और संपत्ति बचाने के लिए नगरों एवं महानगरों में तत्काल समग्र आपदा प्रबंधन व ढांचागत सुधारों की आवश्यकता है। इसमें स्थानीय निकायों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।



अ त्यधिक वाष्णीकरण तथा इसके कारण बादलों में जमा नमी से दुनिया भर में अचानक भारी बरसात के साथ ही समुद्रों का सतही तापमान बढ़ रहा है। ऐसे में अनुकूल परिस्थितियों में भारी बरसात होती है। कई बार पूरे साल भर में होने वाली बरसात 24 से 48 घंटों में हो जाती है। शाहरी ढांचागत संरचनायें इस चुनौती का सामना नहीं कर पाती हैं जिसके कारण इमारतों के भूतल व बेसमेंट में पानी भर जाना सामान्य हो गया है। इसके साथ ही रेल, सड़क व विमान परिवहन प्रभावित होता है जिससे बिजनेसों को नुकसान होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बरसात के कारण फसलें नष्ट होती हैं, भूस्खलन होते हैं तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण जीवन और आजीवका का नुकसान अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार देता है। इससे बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है क्योंकि सार्वजनिक धन को नुकसान पहुंची ढांचागत संरचनाओं के निर्माण पर खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा निजी संपत्तियों के नकसान का मावजा भी



परिवर्तन के कारण होने वाली भारी बरसात तथा बादल फटने जैसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है, पर शहरों की ढांचागत संरचनाओं में समुचित परिवर्तन व सुधार के माध्यम से लोगों की संपत्ति व उनके जीवन को होने वाले नुकसान को बड़ी सीमा तक कम किया जा सकता है। इस संबंध में नगर निगमों को कार्रवाई करने के साथ ही जनता में जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत भी है।

मैं यहां महानगरों के मुद्दों पर गौर करते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। दिल्ली के राजेंद्रनगर में पिछले महीने राव कोचिंग के बेसमेंट में तीन सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले छात्रों की मौत तथा एक और छात्र की बिजली का करेंट लगाने से होने वाली मौत ने स्थानीय संस्था की लापरवाही प्रकट की। हमें उन सावधानियों की जानकारी होनी चाहिए जिसका प्रयोग कर एजेंसियां और इमारतों में रहने वाले लोग यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसी घटनायें फिर न हों। मुंबई नगर निगम ने पहले ही 'स्टार्मावाटर ड्रेन' तथा ऐसी ही ढांचागत संरचनायें तैयार की थीं जो एक घंटे में 25 एमएम बरसात से निपट सकती हैं। पिछले वर्षों में बार-बार आने वाली बाढ़ ने उनको अपनी जलनिकासी व्यवस्था सुधारने के लिए मजबूर किया है जिससे वह 50 एमएम प्रति घंटे की भारी बरसात से निपट सकती है। लेकिन मुंबई, रत्नगिरि,

तारा, महाबलेश्वर व अन्य स्थानों पर उत्तर घंटे 80 से 100 एमएम बरसात तक होती है। इसी प्रकार देश के कुछ अन्य क्षेत्रों अक्सर बादल फटने के कारण प्रति घंटे 100 से चार घंटे तक 80 से 100 एमएम बरसात दर्ज की गई। वायनाड त्रासदी का कारण भी 48 घंटे में 570 एमएम बरसात होता है। इसे देखते हुए मुर्खल, चेनै, हैदराबाद, गुलबज़ार, दिल्ली, गुरुग्राम आदि के नगर गमों को अपनी जल निकासी व्यवस्था सी बनानी चाहिए जो कम से कम प्रति 100 एमएम बरसात से निपट सके। स्टार्टाप्टावाटर डेनों तथा झील की तलहटी ले स्थानों से अवैध कब्जे फैरन हटाने ही है।

इसके साथ ही नालों से मिट्टी यमित रूप से निकाली जानी चाहिए और उनकी सफाई होनी चाहिए ताकि ग्रास्टिक, पालीशीन बैग, सिल्ट आदि छोड़ कर उनको बहुत दूर स्थानों पर फेंका जा सके। शहरों में झीलें जल प्रबंधन में हल्तपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनका जल नियन्त्रित करने के लिए सेल्यूस गेट ने चाहिए। झीलों से मिट्टी तथा सप्तयां निकालने का काम समय-मय पर होना चाहिए। इसके साथ ही उल्ल भंडारों को अधिकतम स्तर तक बच्च रखने का प्रयास होना चाहिए। नालों में जल प्रवेश के सभी स्थानों की यमित निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए होनी चाहिए कि उनमें अशोधित

सीवेज न पहुंचने पाए। इस बात का संभावना है कि तेजी से बढ़ आने वे समय झील का पानी लोगों के घरों में घुस जाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सीवेज का पानी लोगों के घरों में न घुसे। महानगरों में स्टार्टावाटर डेनों पर अक्सर आंशिक रूप से कब्जे हो जाते हैं और लोग मकान या छोटी झोपड़ियां वह बना लेते हैं।

ऐसे कब्जादारों का दूसरी जगह पुनर्वास कर नालों को जल प्रवाह के लिए पूरी तरह खुला रखा जाना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्तमान स्टार्टावाटर डेनें प्रति घंटे 25 एमएम से अधिक बरसात से निपटने में सक्षम नहीं हैं। अनेक शहरी झीलों के जलग्रहण क्षेत्र पर कब्जे हो गए हैं। यह क्षेत्र भारी बात को रोकने तथा जल संरक्षण में सहायता होता है। भंडारण सुविधाओं में कमी के कारण पानी बेसमेंट तथा इमारतों के भूतून में भर जाता है जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसनवंबर, 2015 में 24 घंटे में लगभग 48 एमएम बरसात से चेनै में अब तक कर्ता एक भयावहतम आपदा आई थी। इसमें 500 लोगों की जान गई, 10 लाख मकान पानी में ढूब गए तथा 1.8 मिलियन लोगों को विस्थापित होना पड़ा। इस विभीषिक के दो कारण थे-चेनै में झील के जलग्रहण क्षेत्रों पर कब्जे तथा चेंब्रा बक्कम जल भंडार में जल स्तर नियंत्रित

करने में विलम्ब। इस स्थिति पर इस भंडार से 1.5 लाख क्यूंजे क पानी अडियार नदी में डालने पर ही नियंत्रण हो सका था।

चन्न के अनक 'वेटल्ड' पर वाभन्न समुदायों ने कब्जा कर लिया है। 5000 हेक्टर से अधिक क्षेत्र में फैला पल्लिकरनाई वेटल्ड अब केवल 10 प्रतिशत रह गया है और 500 हेक्टर वेटल्ड ही बचा है। कब्जे न हटाए जाने की स्थिति में भविष्य में ऐसी आपदा से इनकार नहीं किया जा सकता है। स्टार्मवाटर के लिए जलनिकासी पर काम करते हुए नगर निगमों को सीवर लाइनों पर भी ध्यान देना चाहिए। नालों और मैनहोलों को ढंकने पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि कोई व्यक्ति इनमें गिरे नहीं। सड़क पर बाढ़ आने और उसके नदी में बदल जाने पर बिना ढके नाले और सीवर लाइनें लोगों की जान जाने का कारण बनते हैं।

मुबई, पाल्ला, गुरुग्राम व अनक अन्य महानगरों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों के बेसमेंट में भर जाता है। अक्सर इसे पंप से निकाला जाता है जिसमें समय और ऊर्जा खर्च होती है। ऐसे में जमीन में एक 'संप' बनाने की सलाह दी जाती है ताकि बरसात का पानी प्रभावी रूप से नीचे पहुंच जाए। इस प्रकार उसका जल संरक्षण संभव होगा जिसे बाद में अनेक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यदि बेसमेंट साफ रखा जाए तो उसमें एकत्रित बाढ़ का पानी इस्तेमाल योग्य हो सकता है। अनेक नगर निगम नए निर्माण में योजना बनाने के समय 'वाटर हार्वेस्टिंग' ढांचों को अनिवार्य बनाते हैं।

लेकिन क्रियान्वयन के स्तर पर ऐसे ढांचे आमतौर से छोटों से वाटर हार्वेस्टिंग तक सीमित होते हैं और बेसमेंट की अनदेखी करते हैं जहां बादल फटने के समय बाढ़ आने का खतरा सबसे अधिक होता है। ऐसे में बेसमेंट के लिए वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य की जानी चाहिए और इसका गंभीरता से क्रियान्वयन होना चाहिए। आवश्यक होने पर संबंधित नगर निगमों द्वारा इमारत बनाने के नियमों में संशोधन कर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इमारतों के बेसमेंट का प्रयोग केवल वाहन पार्किंग, कबाड़ एकत्र करने तथा वाटर हार्वेस्टिंग या जल धंडारण के लिए हो। किसी भी स्थिति में बेसमेंट का प्रयोग आवास, होटलों और बिजनेसों के लिए नहीं करने देना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा के निहितार्थ



करने के लिए प्रेरित किया है। मोदी की यूक्रेन यात्रा राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

A close-up photograph of Prime Minister Narendra Modi. He is wearing his signature orange kurta and glasses, smiling warmly at the camera. In the background, several other individuals are visible, some appearing to be staff or security personnel. The lighting is bright, typical of indoor event photography.

पेटा किया है। हालांकि, मोदी को यूक्रेन यात्रा दर्शाती है कि भारत की तटस्थता का मतलब निष्क्रियता या रुसी आक्रामकता को मौन स्वीकृति देना नहीं है।

इसके बजाय, यह एक सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो रिश्तों और हितों को संतुलित करते हुए रूस को अपनी सेन्य रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। भारत पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है, खासकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में, जहां चीन की मुख्यता बढ़ती चिंता का विषय है, मोदी की यूक्रेन यात्रा बहुधीयता दुनिया के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को महत्व देता है, अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेता है - एक ऐसा रुख जिसकी कभी-कभी उसके सहयोगियों ने आलोचना की है। मोदी की यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यूक्रेन के पुनर्निर्माण प्रयासों में योगदान देने में भारत की रुचि है। युद्ध ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है, और भारत इसके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में भूमिका निभाने का अवसर देखता है।

यह भागीदारी न केवल एक मानवीय इशारा होगी, बल्कि एक रणनीतिक निवेश भी होगा जो भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभान्वित कर सकता है। अस्ति-स्वार्थी ने योगदान के लिए एक विश्वासी रुख बढ़ाव दिया है, जिसके अनुरूप भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभान्वित कर सकती है। यह एक संबंधित भारतीय उद्योगों को भी लाभ होगा। इसके अलावा, यूक्रेन के पुनर्निर्माण में भारत की भागीदारी चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रति संतुलन के रूप में काम कर सकती है। भागीदार देशों की संप्रभुता का सम्मान करने वाले विकास सहयोग के वैकल्पिक मॉडल की पेशकश करके, भारत खुद को ज़स्तरतंद देशों के लिए ज्यादा अनुकूल भागीदार के रूप में पेश करता है। यह दृष्टिकोण भारत के खुद को वैश्विक नेता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक नैतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने के व्यापक लक्ष्य के साथ संरेखित है। चूंकि दुनिया मोदी की युक्रेन यात्रा पर करीब से नज़र रख रही है, इसलिए सभावित परिणामों का वैश्विक शक्ति गतिशीलता परस्पर दूरगमी प्रभाव पड़ सकता है। अगर मोदी की कूटनीति रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम में योगदान देती है, तो भारत विश्व मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थानिदृत और समस्या समाधानकर्ता के रूप में उभर सकता है। इससे भारत की प्रतिष्ठा एक ऐसे राष्ट्र के रूप में बढ़ेगी जो अपने सिद्धांतों और रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए जटिल भू-व्यापक सम्बन्धों में रोकेंगे।

लड़कियों का बेहतर प्रदर्शन

जम्मू कश्मीर में चुनाव

जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अब बड़ी पार्टीयां घाटी की स्थानीय पार्टीयों से गठजोड़ में लगी है। देश की एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ने नेशनल कॉंफ्रेंस से समझौता किया है। नेशनल कॉंफ्रेंस के बचन पत्र में पहला ही वादा धारा 370 बहाल करना है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर की दूसरी बड़ी पार्टी पीडीपी भी धारा 370 बहाल करने के एजेंडे के साथ चुनाव मैदान में है। ऐसे में कांग्रेस से यह सवाल पूछना उचित होगा कि अनुच्छेद 370 के बारे में उसकी क्या राय है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर को पुराने अंधकारमय समय में धकेलना चाहती है, जब वहाँ आतंकवादियों, अलगाववादियों, जिहादियों और पत्थरबाजों का राज था? वैसे तो अनुच्छेद 370 की बापसी लगभग असंभव है, पर सत्ता के लालच में ढूबी पार्टीयां इसे लेकर अव्यवस्था, अराजकता व अशांति पैदा करने का प्रयास कर सकती हैं। ऐसे में भाजपा को जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र रूप से अकेले ही विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। कश्मीर घाटी में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए भाजपा ऐसी छोटी पार्टीयों से समझौता कर सकती है जो जम्मू कश्मीर को विकास

पर सहमत हों।

परेशान कश्मीरी नेता

नेशनल कान्फ्रेंस अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर के लोग बरसों से कठिनाई में हैं। लेकिन वास्तव में जनता के बजाय अब्दुल्ला जैसे नेता ही कठिनाई में हैं। उन्हें याद करना चाहिए कि 1991 में बहुत से लोगों ने जम्मू-कश्मीर छोड़ा था, जबकि अनुच्छेद 370 व 35 ए हटने के बाद से पूरे देश से लोगों वहां बसते जा रहे हैं और आतंक बहुत कम हो गया है। अप्पे है कि वहां लोग कठिनाई में नहीं हैं बल्कि जिनकी सत्ता के बरहे लोग कठिनाई में थे वे बिना सत्ता के तड़प रहे हैं। बरसों से सत्ता सुख भोगने व शाही ठाटबाट से रहने वालों का सुखचैन जो नल्ला गया है। इनमें कांग्रेस

नेशनल कांप्रेस, पीडीपी व अन्य दलों के नेता शामिल हैं प्रधानमंत्री मोदी अपने सपने विकासित भारत का लक्ष्य पूरा करने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें कश्मीर कंधे से कंधा मिला कर सबके साथ है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के परेशान नेता किसी न किसी तरह जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। हलिया संसदीय चुनाव में जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने दिखा दिया है कि वे बदलते भारत और बदलते कश्मीर से बहुत खुश हैं। इससे विपक्षी नेताओं की नींद उड़ गई है और अब्दुल्ला के बयान या विलाप की यही कारण है।

मुजीबुर रहमान की रमृति

बांगलादेश में नरसंहार और राजनीतिक घटनाओं की जांच संयुक्त राष्ट्रसंघ की विशेष टीम अगले सप्ताह करेगी। इससे पहले यह टीम 1971 में बांगलादेश मुक्ति संग्राम में हुए मानवीय अत्याचारों की जांच करने आई थी। इसके कारण बांगलादेश में राजनीतिक घटनाओं पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। बांगलादेश के निर्माण के मुख्य नेता और शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 15 अगस्त 1975 को हत्या कर दी गई थी। इसलिए इस दिन बांगलादेश में सार्वजनिक अवकाश होता है। लेकिन मौजूदा मुहम्मद यूनुस सरकार ने अवामी लीग और अन्य दलों से पूछे बिना ही इस राष्ट्रीय अवकाश को रद्द कर दिया है। यह एक प्रकार से बांगलादेश के मुक्ति संग्राम और उसके नायक शेख मुजीबुर रहमान की स्मृति मिटाने या उसे धूंधली करने की चाल है। यूनुस सरकार ने शेख हसीना और उनके कैबिनेट सहयोगियों पर अनेक मुकदमे थोपने के साथ ही उनका राजनीतिक यासपोर्ट भी रद्द कर दिया है। ऐसे में शेख हसीना भारत में ही रहने को मजबूर होंगी। बांगलादेश में जारी यह उथलपुथल भारत की चिन्ता का विषय है।

- दत्तप्रसाद शिरोड़कर, मुर्बंड

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भेज सकते हैं।

जनता को जनार्दन मानकर आगे बढ़ने वाली सत्ता के निर्णय होते हैं लोकप्रिय

पायनियर समाचार सेवा।



स्तर पर इसे महसूस किया है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को गांधियाबाद में एक मीटिंग में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। योगी ने कहा कि भारत को लोकतंत्र की अपनाया हो पर न्यायपालिका, कानूनपालिका व विधायिका की भी अपनी लक्षण रेखा है, लेकिन चौथे स्तर के रूप में मीडिया की भूमिका को कोई नजर नहीं कर सकता है। लोगों को सही तर्थों से अवशत करना, सही जानकारी उपलब्ध कराना, अवश्यकता पड़ने पर किसी बड़े औपरेशन का नेतृत्व करना और आर लेखनी के माध्यम से किसी का पोस्टमार्टम भी करना है। हमने आजदी के बाद भी हो तो मीडिया की भूमिका दिखती अलग-अलग समय के अनुरूप बदलना और

चलना होगा। समाज, युवा, सामान्य जूहस्थ, किसान, आधी आबादी की अवश्यकता क्या है, मीडिया उनके पास के अनुरूप जनाकरी उपलब्ध करा सके। एक समय था, जब लोग मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से देश-दुनिया की घटनाओं के देखते लोकतंत्र में हो रहे हैं। ऐतिहासिक वैयाकित्व का लोकतंत्र एसे हैं कि अनेक वेडिंगों, समाचार पत्रों के सबसे बड़े लोकप्रिय खबरों को मिलते हैं, जब आम जनभावनाओं को सबोंपरि रखकर उस समय की राजसत्ता ने निर्णय लेने में कोई संकेत नहीं किया। जनता को जनार्दन मानकर जब भी शासन सत्ता आगे बढ़ती है तो उसके निर्णय लोकप्रिय, सर्वमान्य व सर्वग्राह्य बनते हैं।

सीएम योगी ने कहा कि हमें समय के अनुरूप बदलना और

मीडिया की भूमिका कुछ गौण हो, डिजिटल मीडिया और प्रभावी हो आज इस चैनल का शोधाभ हो रहा है। मुझे विश्वास है कि भारत के लोकतंत्र के अनुरूप खबरों को प्रयोग भारतवासी तक प्रभावी हो जाए, जब दोनों मीडिया में अनेक चैनल एए, जब तो एसे के साथ प्रचार-उदाहरण देखो को मिलते हैं, जब आम जनभावनाओं को सबोंपरि रखकर उस समय की राजसत्ता ने निर्णय लेने में कोई संकेत नहीं किया। जनता को जनार्दन मानकर जब भी शासन सत्ता आगे बढ़ती है तो उसके निर्णय लोकप्रिय, सर्वमान्य व सर्वग्राह्य बनते हैं।

सीएम ने कहा कि इस चुनाव में हमने फिर डिजिटल व सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के प्रभावित कर रहे थे। आपसे दो-पांच वर्ष में जब हम चुनाव में जाएंगे तो हो सकता है कि प्रिंट व विजुअल

देश के सबसे युवा राज्य में मुख्यमंत्री का सर्वाधिक जोर स्वयोजनाएं पर

● योगीओं को प्रशिक्षण देकर कौशल नियाएं और आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी में घल रही कई योगनाएं पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी का शुरू से ही जोर स्वयोजनाएं में उपराष्ट्रपत्री और आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर लिखा कि उपराष्ट्रपत्री जगदीप धनवड़ से नई दिल्ली में शिश्वाचार भेट की। सीएम योगी ने सुबह उपराष्ट्रपत्री के आवास पर पहुंचकर उनका हाल चालना लिया। वहाँ से उपराष्ट्रपत्री ने अपने बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए सर्वोच्च जगदीप धनवड़ को देखा। दूसरी तरफ, उपराष्ट्रपत्री के 'एक्स' हैंडबुक से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास मांडल की प्रशंसा की। उपराष्ट्रपत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की फोटो पोस्ट करते हुए जानकारी दी गई।

कार्यक्रम, विश्वकर्मा श्रम समान योग्या, स्टर्टअप पॉलिसी, एपएसएपर्फॉर्मेंस को प्रोत्साहन देती ही योगनाएं हैं जिनके जरूरी उत्तर प्रदेश अपनी अधिक्यवस्था का कार्याकलृत करते हैं। एक तरफ प्रदेश में इवेस्टर्स संचित के जरूरी कई नामांचन इंस्ट्रियुल घराने और खुद ग्रामीण भौमिका के लोकांशक्ति को अप्राप्ति करते हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया के डिफेंसर्स सेवकर इसका प्रमाण है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया की विशेषता को अप्राप्ति करते हैं। योगी की युवाओं को उत्कृष्ण करने के अनुरूप धनवड़ को शासन करने के लिए उत्तर प्रदेश व्यापार करना चाहता है। उन्हें कई लाभ होंगे। प्रशिक्षण युवाओं की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्याजार में श्रम की कीमत बढ़ जाएगी। प्रशिक्षण प्राप्त की युवा स्थानीय अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए सर्वोच्च जगदीप धनवड़ को देखा। दूसरी तरफ व्यापार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय व्यापार की विभिन्न विवरण देखते हैं। योगी की युवाओं को अप्राप्ति करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय व्यापार की विभिन्न विवरण देखते हैं।

● मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपत्री से मिलकर जताया आमादा

योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर लिखा कि उपराष्ट्रपत्री जगदीप धनवड़ से नई दिल्ली में शिश्वाचार भेट की। उनका योगी ने सुबह उपराष्ट्रपत्री के आवास पर पहुंचकर उनका हाल चालना लिया। उन्होंने इवांस द्वारा देखा जाना चाहता है। उन्हें कई लाभ होंगे। प्रशिक्षण युवाओं की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्याजार में श्रम की कीमत बढ़ जाएगी। प्रशिक्षण प्राप्त की युवा स्थानीय अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए सर्वोच्च जगदीप धनवड़ को देखा। दूसरी तरफ, उपराष्ट्रपत्री के 'एक्स' हैंडबुक से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास मांडल की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री

राष्ट्रीय युवाओं को अप्राप्ति करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय व्यापार की विभिन्न विवरण देखते हैं। योगी की युवाओं को अप्राप्ति करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय व्यापार की विभिन्न विवरण देखते हैं।

माजपा कार्यकर्ता हताश होकर बूथ छोड़कर भाग चुका है: अधिकारी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

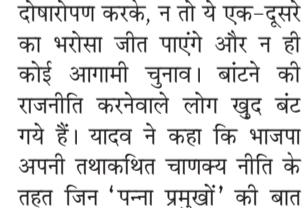


गये? अज आम वे उपलब्ध नहीं हैं तो उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। अब भाजपा के जो गिने-चुने कार्यकर्ता बाज़ार हैं। वे ये सोचकर हताश हैं कि वर्तमान परिस्थिति में अनुरूप धनवड़ को अप्राप्ति करना चाहता है। उन्हें कई लाभ होंगे। प्रशिक्षण युवाओं की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्याजार में श्रम की कीमत बढ़ जाएगी। प्रशिक्षण प्राप्त की युवा स्थानीय अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए सर्वोच्च जगदीप धनवड़ को देखा। दूसरी तरफ, उपराष्ट्रपत्री के 'एक्स' हैंडबुक से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास मांडल की प्रशंसा की। उन्होंने फिर डिफेंसर्स सेवकर इसका प्रमाण है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया के डिफेंसर्स सेवकर इसका प्रमाण है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया की विभिन्न विवरण देखते हैं। योगी की युवाओं को अप्राप्ति करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय व्यापार की विभिन्न विवरण देखते हैं।

राष्ट्रीय युवाओं को अप्राप्ति करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय व्यापार की विभिन्न विवरण देखते हैं। योगी की युवाओं को अप्राप्ति करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय व्यापार की विभिन्न विवरण देखते हैं।

भाजपा कार्यकर्ता हताश होकर बूथ छोड़कर भाग चुका है: अधिकारी

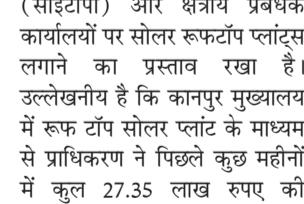
पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ



गये? अज आम वे उपलब्ध नहीं हैं तो उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। अब भाजपा के जो गिने-चुने कार्यकर्ता बाज़ार हैं। वे ये सोचकर हताश हैं कि वर्तमान परिस्थिति में अनुरूप धनवड़ को अप्राप्ति करना चाहता है। उन्हें कई लाभ होंगे। प्रशिक्षण युवाओं की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्याजार में श्रम की कीमत बढ़ जाएगी। प्रशिक्षण प्राप्त की युवा स्थानीय अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए सर्वोच्च जगदीप धनवड़ को देखा। दूसरी तरफ, उपराष्ट्रपत्री के 'एक्स' हैंडबुक से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास मांडल की प्रशंसा की। उन्होंने फिर डिफेंसर्स सेवकर इसका प्रमाण है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया के डिफेंसर्स सेवकर इसका प्रमाण है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया की विभिन्न विवरण देखते हैं। योगी की युवाओं को अप्राप्ति करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय व्यापार की विभिन्न विवरण देखते हैं।

औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे रुफ टॉप सोलर प्लाट

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/कानपुर



(सीईटीपी) और क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालयों पर सोलर रुफटॉप प्लाट्स के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इसके अनुरूप धनवड़ को सत्र अदालत ने सात वर्ष की मिलती वार्षिकता के अनुरूप धनवड़ को अप्राप्ति करना चाहता है। उन्होंने इसका विवरण देखा। उन्होंने कहा कि यह अपने अनुरूप धनवड़ को अप्राप्ति करना चाहता है। उन्होंने कहा कि यह अपने अनुरूप धनवड़ को अप्राप्ति करना चाहता है। उन्होंने कहा कि यह अपने अनुरूप धनवड़ को अप्राप्ति करना चाहता है। उन्होंने कहा कि यह अपने अनुरूप धनवड़ को अप्राप्ति करना चाहता है।

उत्तर प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए योगी सोलर रुफटॉप प्लाट्स के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इसके अनुरूप धनवड़ को अप्राप्ति करना चाहता है। उन्होंने कहा कि

